

प्रपत्र -23

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- बष्टी

तहसील - ऊखीमठ , जिला - रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण। राज्य वन भूमि 0.450 है। अर्थात् कुल 0.450 है। वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बष्टी द्वारा दिनांक 15/12/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बष्टी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



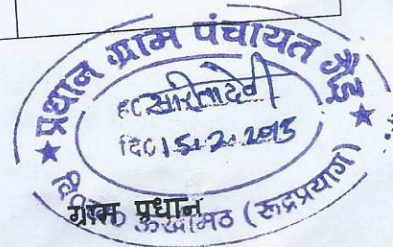
ग्राम प्रधान

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड से बष्ठी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दिनांक _____ को ग्राम / सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - बष्ठी

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री. बलवीर सिंह	Balvir Singh
2	श्री. विजय सिंह	विजय सिंह
3	श्री. विमला देवी	विमला देवी
4	श्री. सरिता देवी	सरिता देवी
5	श्री. राजेश्वरी देवी	राजेश्वरी देवी
6	श्री. कीशती देवी	कीशती देवी
7		
8		
9		
10		



परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, - ऊखीमठ

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण- पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, - ऊखीमठ**

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण। पंचायती वन भूमि 0.650 है, अर्थात् कुल (0.650) है। वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील -ऊखीमठ) की दिनांक 8/05/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता श्री उत्तम सिंह चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| 1- श्री <u>उत्तम सिंह चौहान</u> | उपजिलाधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>अनूप कुमार</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | सदस्य |
| 3- श्री <u>रविंद्र कुमार</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>ऊखीमठ</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>रविंद्र कुमार</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | <u>ऊखीमठ</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना हेतु (0.650) है। राज्य वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

[Signature]
8/5/15

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड - ऊखीमठ परिक्षेत्र के जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड से बण्टी-गडगू मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु (0.650) है. राज्य वनभूमि का लो.नि.वि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1.

2.

3.

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
उप वन प्रभाग

श्रीमती सगीता दत्त
सदस्य
क्षेत्र पं० गैड, गडगू
वि० ख० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक वन विकास अधिकारी-जिला
विकास खण्ड ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - ऊखीमठ

जनपद - रुद्रप्रयाग

No- R-15/ST-विधि/2015 दि० 08/05/2015

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - ऊखीमठ

जनपद - रुद्रप्रयाग

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.S

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar District Magistrate Rudraprayag on date 24/6/15 at time 2:00 P.M. at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.650 hect for Transfer of Gaid to Basti-Gadgu Motor Road under Sate sector of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division 35 level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:.. 24.6.15


 (Dr. Raghav Langar)
 District Magistrate-cum-
 Chairman, District Level
 Committee, Rudraprayag

58

Form-I

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District collector- Rudraprayag

No. 80

Dated 24/6/15

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (0.650) hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Ukhimath Rudraprayag (name of user agency) for Construction of gale to basti-gadgu Motor Road, (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag - district falls within jurisdiction of basti villages in Ukhimath tehsil

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire (0.650) Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure 1 and annexure 2.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre-agricultural communities.

Encl As above.

(Full name and official seal of the District collector)


Signature
District Collector
Rudraprayag